जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 33 संख्याः 4 प्रभात उदयपुर, बुधवार, 5 नवम्बर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल गाँधी की, फ्रैश, साफ छवि वाले जिलाध्यक्ष बनाने की योजना राजस्थान में क्यों फेल हो रही है

यह कार्यक्रम देश भर में जोर-शोर से आगे बढ़ रहा है, पर, राजस्थान में आकर फिसड्डी हो गया है

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान शुरू कर साफ-सुथरी और प्रभावी राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस अभियान के तहत, जिलाध्यक्षों को अधिक अधिकार और मजबूती देने के लिए कुछ मानक और नियम तय किए गए हैं, ताकि संगठन के संचालन में ऊर्जा और प्रभावशीलता बनी रहे। यह प्रक्रिया पूरे देश के कई राज्यों में चल रही है।

- राजस्थान में यह दो व्यक्तियों के कारण असफल होता नज़र आ रहा है। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व प्रभारी रंधावा।
- स्पष्ट निर्देश थे कि दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो खोजबीन व छानबीन के बाद, नए जिलाध्यक्षों के नाम प्रस्तावित करेंगे।
- यह भी स्पष्ट निर्देश थे कि प्रदेशाध्यक्ष व राज प्रभारी की इन नियुक्तियों में कोई भूमिका नहीं होगी।
- पर, प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी ने बारह नामों की सूची भेजी है। इस सूची में वे नाम शामिल हैं, जो काफी हद तक विवादित हैं, जैसे प्रमोद सिसोदिया चित्तौड़गढ़, शबनम गोदारा हनुमानगढ़ तथा पुष्पेंद्र भारद्वाज जयपुर। इस तरह के कई नाम हैं, जो पुराने नेताओं व खेमेबाजी में भी सक्रिय रहे हैं।

इस कार्य के लिए पर्यवेक्षकों (ऑब्ज़र्वर्स) को नियुक्त किया गया है, जिन्हें राज्य नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्षों और अन्य स्वार्थी हितों को दरकिनार करते हुए, जिलाध्यक्षों के नामों की पैनल सूची तैयार करनी थी।

लेकिन राजस्थान में इन निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। केन्द्र से मिले स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी करते हुए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और एआईसीसी प्रभारी रंधावा ने 12 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेज दी हैं, जबकि, इसका अधिकार नहीं था तथा ऐसा न करने के निर्देश उन्हें पहले ही दे दिए गए थे, क्योंकि इस काम के लिए अलग से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम सुझाए गए हैं, उनमें कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि स्वच्छ छवि और प्रभावी जिलाध्यक्षों की मूल भावना के खिलाफ हैं। रंधावा, जिन्हें राजस्थान का प्रभारी बनाए रखा गया है, केसी वेणुगोपाल के करीबी माने जाते हैं, और वेणुगोपाल पार्टी में वास्तविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।

रंधावा, डोटासरा, अशोक गहलोत और सी.पी. जोशी के गुट से जुड़े हुए हैं। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और ऐसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये'

जयपुर, 4 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार से 6 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए यह बताने के लिए कहा है कि अभी तक सड़क सुरक्षा नीति, ब्लैक स्पॉट सुधार योजना और वाहन जांच अभियान के तहत क्या कदम उठाए गए हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की

- राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर प्रसंज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने 6 नवंबर तक जवाब मांगा।

खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है।

याचिका में कहा गया कि हाल में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित प्रदेशभर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें लोगों की मौतें हुई है। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सड़क सुरक्षा के प्रति सरकारी लापरवाही, खस्ताहाल रोड, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की कमी और ट्रैफिक प्रबंधन की विफलता है। प्रदेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एनडीए का आंतरिक फीडबैक, पटना में भारी झटका लग सकता है

एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 2020 में भाजपा ने पटना की 14 में से 9 सीटें जीती थीं, इस बार 3 या 4 सीटें ही मिलेंगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त होने के साथ ही राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है, जिससे सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर की संभावना बन गई है।

जैसे-जैसे तस्वीर साफ हो रही है, शुरुआती जमीनी आकलन यह संकेत दे रहे हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव संभव है, खासकर पटना जिले में, जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गढ़ माना जाता रहा है।

- पटना में पहले चरण में मतदान होना है। नुकसान को भांपते हुए प्रधानमंत्री ने खुद पटना की चुनावी मुहिम संभाली और विशाल रोड शो के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, पर, अभी अनिश्चितता कायम है।
- राजनैतिक जानकारों ने कहा कि यह बदलता रुख सत्ता विरोधी लहर, बेरोज़गारी की चिंता और महागठबंधन के बढ़ते प्रभाव की वजह से है।
- इन हालात में भाजपा की नज़र में नीतीश का मोल बढ़ गया है, भाजपा में। माना जा रहा है कि तेजस्वी को हराने के लिए नीतीश की जरुरत पहले से कहीं ज्यादा है।

एनडीए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने आंतरिक फीडबैक का हवाला देते हुए माना कि राज्य के राजधानी क्षेत्र में भाजपा को अप्रत्याशित झटका लग सकता है। पटना जिले की कुल 14 विधानसभा सीटों में से, जहां 2020 के चुनाव में भाजपा ने 9 सीटें जीती थीं, इस बार पार्टी को महज 3 से 4 सीटों पर ही जीत मिलने का अनुमान है। इसलिए 6 नवंबर को होने वाला पहला चरण पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जिसने इस जिले में अपने संगठन और स्टार प्रचारकों की पूरी ताकत झोंक दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से पटना में भाजपा की चुनावी मुहिम की कमान संभाली, विशाल रोड शो और जोशीली जनसभा के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन इन जबरदस्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

7 देशों के डिप्लोमैट्स की टीम चुनाव देखने बिहार गई

''नो भाजपा'' (भाजपा को जानो) मुहिम के तहत दो दिन के प्रवास में इन डिप्लोमैट्स ने भाजपा के चुनाव प्रचार को करीब से देखा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा शुरू की गई ''नो बीजेपी'' (भाजपा को जानो) पहल के तहत जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के भारत में स्थित दूतावासों के राजनयिक प्रतिनिधियों का एक दल 2-3 नवम्बर 2025 को बिहार का दौरा करने के लिए गया, ताकि वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार और भारत की जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकें।

- बिहार यात्रा में इन राजनयिकों ने प्र.मंत्री मोदी की आरा में हुई विशाल जनसभा देखी, कई-कई नेताओं से मुलाकात की तथा घर-घर चुनाव अभियान में गहरी रूचि ली।
- ''नो भाजपा'' मुहिम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने शुरु की है।
- डिप्लोमैट्स की टीम में जापान, यूनाईटेड किंगडम, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान व भूटान के राजनयिक शामिल थे।

इस प्रतिनिधिमंडल ने अररिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सार्वजनिक रैली देखी, जहाँ उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे लोगों की भागीदारी को देखा। अपने दौरे के दौरान, राजनयिकों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं रविशंकर प्रसाद, धर्मेन्द्र प्रधान और विनोद तावड़े से मुलाकात की और बुनियादी स्तर पर घर-घर जाकर हो रहे चुनाव प्रचार की गतिविधियों को देखा। इसके बाद वे भाजपा के राज्य मुख्यालय पटना गए और पार्टी के संगठन, संचार रणनीति और चुनाव प्रबंधन प्रणाली को समझने के लिए राज्य के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की।

एस आई भर्ती : अशोक गहलोत के पूर्व पी एस ओ को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 4 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ रहे राजकुमार यादव सहित पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ अदालत ने पीएसओ के बेटे

- हाई कोर्ट ने पीएसओ के पुत्र सहित नौ आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये।

भरत यादव सहित नौ आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश 14 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने पेपर लीक गैंग के सदस्य विजय कुमार डामोर, पेपर हल करने वाले प्रवीण कुमार, सत्येन्द्र यादव, ट्रेनी एसआई समेता कुमारी और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जद (यू) के कद्दावर नेता लल्लन सिंह पर चुनाव आयोग ने केस किया

लल्लन सिंह एक वायरल वीडियो में धमकाने वाला बयान देते हुए दिखे कि मतदान के दिन कुछ नेताओं को घर से नहीं निकलने देना है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। बिहार में पहले चरण के हाई-वोल्टेज विधानसभा चुनाव में वोटिंग से 48 घंटे पहले, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू में नंबर 2 और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ एक पुलिस मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उनके चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने को लेकर दर्ज हुआ है।

लल्लन सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वह एक वीडियो में यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि ''कुछ नेताओं को मतदान के दिन उनके घर से बाहर जाने नहीं दिया जाना चाहिए।'' यह एफआईआर चुनाव आयोग के आदेशों पर आर भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

- लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह खुद एक बाहुबली हैं तथा नीतीश के करीबी हैं। जद (यू) में उन्हें नीतीश के बाद नंबर दो माना जाता है।
- मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल ने मोकामा में दिए गए लल्लन सिंह के भाषण का वीडियो जारी किया।
- मोकामा लल्लन सिंह के लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में आता है, जहाँ से जद (यू) ने बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया है। लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, जो खुद बाहुबली हैं, अनंत सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं।
- लल्लन सिंह ने दुलार सिंह यादव (एक अन्य पूर्व बाहुबली) की हत्या में अनंत सिंह का बचाव किया व कहा कि अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है।

मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लल्लन सिंह के भाषण का मुद्दा उठाया था, जो उस वक्त सुर्खियों में आया था जब स्थानीय बाहुबली और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

वायरल वीडियो में लल्लन सिंह यह कहते सुनाई दे रहे हैं, ''कुछ नेताओं को चुनाव के दिन उनके घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर वे बहुत ज़्यादा मांग करें, तो उन्हें अपने साथ ले जाओ और मतदान करने के बाद उन्हें घर वापस लेकर जाओ और बिस्तर पर सुला दो। उन्हें घर में बंद कर देना है। अब जिम्मेदारी संभालो। चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा है।''

वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने कहा कि लल्लन सिंह चुनाव आयोग पर बुलडोजर चला रहे हैं। ''(वह कह रहे हैं) उन्हें बंद कर दो, अगर वे मिन्नत करें तो उन्हें मतदान करने ले जाओ। आरजेडी ने सवाल उठाया, मरा हुआ आयोग कहाँ है?''

मोकामा, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लल्लन सिंह के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में आता है। इससे पहले, एक साक्षात्कार में उन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को एक साजिश बताया था और कहा था कि आगामी चुनावों में बाहुबली अनंत सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पैसेंजर ट्रेन व मालगाड़ी की टक्कर में 7 की मौत

बिलासपुर, 04 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को एक मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गयी, जिसमें सात यात्रियों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये।

दुर्घटना बिलासपुर स्टेशन के पास शाम को करीब चार बजे हुयी जिसमें

- बिलासपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकराई।

मेमू ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गयी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गयीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूमिहार बिहार में जनसंख्या का 2.9 प्रतिशत ही हैं

फिर एनडीए ने बत्तीस व महागठबंधन ने पंद्रह भूमिहार नेताओं को क्यों टिकट दिये हैं, विधानसभा चुनावों में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। भूमिहार बिहार की जनसंख्या का केवल 2.9 प्रतिशत हैं, लेकिन एनडीए ने 32 और महागठबंधन ने 15 भूमिहारों को टिकट दिया है। आज, भूमिहार बिहार में महत्वपूर्ण जाति बन गए हैं।

बिहार के केन्द्र में, गंगा नदी के किनारे स्थित मोकामा एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, जो पहले एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था और एक प्रमुख दाल उत्पादन केन्द्र था।

आज, मोकामा एक क्रूर विडंबना के रूप में हमारे सामने है तथा अपराध और राजनीति के जटिल अंतर्संबंध का प्रमाण बना हुआ है। इस क्षेत्र में अतीत और वर्तमान एक भयंकर हिंसा, शक्ति और चुनावी महत्वाकांक्षा के विभिन्न जीवन्त स्वरूप में दिखाई देते हैं।

जैसे-जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, पुराने प्रतिद्वंद्वियों के बीच की खाई नए आरोपों के बीच उभरकर सामने आई है। हाल ही में, 64 वर्षीय भूमिहार उम्मीदवार अनंत सिंह, जो जेडी (यू) से हैं, की गिरफ्तारी 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की हत्या से संबंधित आरोपों में हुई, जो खुद भी पहले एक गैंगस्टर थे, फिर राजनीति में आए थे। यह गिरफ्तारी इस उथल-पुथल भरे क्षेत्र में बाहुबली नेताओं के निरंतर प्रभाव को उजागर करती है, और अनंत सिंह के लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रहे सूरज भान सिंह के खिलाफ एक तीव्र मुकाबला फिर से शुरू हो गया है। सूरज भान सिंह भी एक कुख्यात भूमिहार एवं बाहुबली नेता हैं।

मोकामा, जो पटना से केवल 70 किलोमीटर दूर स्थित है, एक ऐसे खूनी इतिहास से जूझ रहा है, जो इसके राजनीतिक रूप से ताकतवर व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अनंत सिंह और सूरज भान सिंह, दोनों भूमिहार जाति के कुख्यात व्यक्ति, दशकों से एक हिंसा के उस चक्र में फंसे हुए हैं, जो 1980 के दशक से शुरू हुआ। उनका

- इस प्रश्न का जवाब है, बिहार के इतिहास में, ऐतिहासिक व सामाजिक जीवन में भूमिहार जाति का भारी प्रभाव रहा है।
- भूमिहार मुख्य रूप से लैंड ओनिंग जाति है और कई छोटे-बड़े राजघरानों में, जैसे बेतिया, टिकारी, हथुआ, तामुखी, श्योहर, पाकुर, महिषादल, महेशपुर व वाराणसी, भूमिहार ठिकाने हैं।
- बिहार में भूमिहारों ने कई बुद्धिजीवी, जैसे, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांस्कृतायन, रामवृक्ष बेनीपुरी भी दिये बिहार को।
- राजनीतिक दृष्टि से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, भूमिहर नेता कृष्ण सिन्हा (1946-61) थे, उनके लंबे राजनीतिक जीवन में कई प्रभावशाली भूमिहार नेता पनपे। जैसे, महेश प्रसाद सिन्हा, कैलाशपति मिश्रा, वर्तमान में सी.पी. ठाकुर, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा।
- बुद्धिजीवी लैंड ओनिंग जाति, राजनीति व प्रशासनिक बिहार में बहुत महत्व रखती है। वर्ष 1990 से 2025 तक, नीतीश-लालू युग में सत्ता जरुर इन दोनों के इर्द-गिर्द रही, पर, प्रशासनिक पकड़, उच्च शिक्षा, मीडिया, प्रोफेशनल, जैसे कानून व मैडिसन आदि में भूमिहार छाये रहे।

अतीत गोलीबारी और खून-खराबे से भरा हुआ है, क्योंकि ये लोग सत्ता में अपने बाहुबल और धमकियों के जरिए एक ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में पहुँच गये थे, जहाँ बाहुबल अक्सर रणनीति पर हावी रहती थी।

हाल ही में, जन सूराज समर्थक पार्टी के दुलारचंद यादव की हत्या (जो लालू प्रसाद के पुराने सहयोगी थे) ने राजनीतिक गुटों के बीच झड़पों के बीच मोकामा की समकालीन कहानी में एक और काला अध्याय जोड़ दिया। यह घटना, जिसमें अनंत सिंह के समर्थक शामिल थे, न केवल इस क्षेत्र में राजनीतिक जीवन के खतरों को उजागर करती है, बल्कि इस क्षेत्र की निर्दयी राजनीति के रूप को भी एक भयंकर रूप में प्रस्तुत करती है।

जैसे-जैसे पुलिस यादव की मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है, शहर अपनी सांस रोके हुए, अपने हिंसक अतीत और चुनावी बदलाव के अनिश्चित वादे के बीच फंसा हुआ है।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक अजीब परिवर्तन दिखता है, एक ऐसा परिदृश्य, जहां पूर्व दुश्मन अब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारह राज्यों में एसआईआर का काम शुरू

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। चुनाव आयोग ने कहा कि 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम शुरू हो गया है।

चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को बताया गया कि बिहार में

- चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की।

एसआईआर के सफल समापन के बाद, इस अभ्यास के दूसरे चरण में नौ राज्यों (छत्तीसगढ़ , गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इसमें तीन केन्द्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी) के 321 जिले और 1,843 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि इन 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK